SHRI MANJUNATH KUNNUR (DHARWAD SOUTH): Sir, I would like to bring to the kind attention of the hon. Minister for Agriculture that the people of Karnataka have suffered from heavy rainfall and the consequent floods in many regions. The maximum damage has been caused in Belgaum, Bijapur, and in many parts of North Karnataka. About 13000 villages have been affected and 130 people have lost their precious lives in the floods. Over 11,000 cattle have been killed. Over 90,000 houses got damaged and standing crops spreading over four lakh acres have been washed away. Public property including roads, buildings and bridges have also been damaged. The natural calamity has caused a huge loss of over Rs.3500 crore.

In Haveri District of my parliamentary constituency, due to heavy rainfall and floods in many talukas, maize, chillies, groundnut, jawar and other crops have been damaged. I would request that an amount of Rs.10,000 per acre may please be given by the Government of India.

Under the circumstances, I urge upon the Government of India to release a further sum of Rs.3500 crore and also announce a special package for the State of Karnataka, as was done for the Tsunami affected coastal areas of the country. Crop loan and interest burden of the farmers for the current year may also please be waived, which would help the farmers to tide over the crisis due to heavy rains and floods.

MR. SPEAKER: You have raised a very important matter.

. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Mr. Uday Singh, you have to have patience.

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, जिला पिथौरागड़ में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण, 6300 मैगावाट क्षमता के विद्युत प्रोजैक्ट रुक चुके हैं और लगभग 20-25 वर्षों से मदकोट ब्लॉक मुन्स्यारी और सोबला फैज-दो पैंडिंग है, जबकि बॉटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दोनों ने इसे रिक्मैंड किया था और इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला है। इसमें 115 रैवेन्यू विलेजेज हैं। कस्तूरी मृग विहार घोषित होने के कारण वहां विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इन

ग्रामों को वन संरक्षण अधिनियम की परिधि से बाहर किया जाए और दोनों प्रोजैक्ट्स को तत्काल मंजूरी दी जाए, ताकि वहां विद्युत का उत्पादन शीघ्र हो सके।

श्री भँवर सिंह डांगावास (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी सत्र में करीब दस दिन पहले आग्रह किया था कि राजस्थान के नागौर जिले में अकाल की स्थिति बन रही है और आज यह स्थिति है कि अधिकतर क्षेत्रों में खरीफ की फसल या तो बोई नहीं गई और अगर बोई गई तो पुनः बरसात नहीं होने के कारण वह सूख रही है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि बुआई में जो उनका खर्च हुआ, वह सब बर्बाद हो गया। पूरे क्षेत्र से पशुपालक पलायन कर रहे हैं और किसान भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। कुछ फसलों जैसे, कपास आदि को कुओं की सिंचाई से बचाया जा सकता था, परंतु विद्युत आपूर्ति भी पूर्णरूपेण नहीं मिल रही है, क्योंकि राज्य में विद्युत उत्पादन राज्य के लिए पर्याप्त नहीं है। मैंने नागौर जिले में यूसीजी भूमिगत कोयले को जलाकर विद्युत उत्पादन करने की बात उर्जा मंत्री जी से कही थी, लेकिन उन्होंने पूरा उत्तर न देकर साधारण तौर पर कह दिया कि हो जाएगा। महोदय, इस योजना की ओर ध्यान दें, तो उचित रहेगा।

नदियों को जोड़ने की योजना का लाभ सबसे पहले राजस्थान को मिलना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि इस भीषण अकाल में राहत कार्य आरंभ करें तथा सूखे और भुखमरी से मर रही जनता को आत्मदाह से बचाने की कृपा करें और धन की सहायता दें, जिस प्रकार से स्पेशल पैकेज सुनामी व मुंबई में बाढ़ के तहत दिए गए हैं, उसी तरह यहां भी सहायता सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद।

MR. SPEAKER: Shri Sunil Khan, you are allowed to raise only one matter and that is about the BBUNL.

SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR): Sir, the BBUNL is the holding company of M/s BSCL, Burnpur and M/s Braithwaite. Now, on the one hand, the closure of M/s BSCL, Burnpur has been recommended, but on the other hand, twenty